

प्रेषक,

डॉ० एम०सी० जोशी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
अर्थ एवं संख्या,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 26 नवम्बर, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में एन०आई०सी० ऑफिस, सचिवालय परिसर के मेन्टनेंस हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में आपके पत्र सं०-1720/3-ले०-1(1)/बजट/2015-16, दिनांक 03.11.2015 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-7 के अधीन लेखाशीर्षक-3454-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-एन०आई०सी० स्टेट यूनिट को अनुदान की मद सं०-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत राज्य सूचना विज्ञान कार्यालय सचिवालय परिसर, देहरादून के मेन्टनेंस हेतु प्राविधानित बजट ₹ 200 हजार (₹ दो लाख मात्र) की धनराशि वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- 1- धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं०-400, दिनांक 01.04.2015 के प्राविधानों के अधीन ही सुनिश्चित किया जाय।
- 2- उक्त स्वीकृति के क्रम में अनुक्षण कार्यों के संपादन हेतु धनराशि का व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानान्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायगा।
- 3- प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि आप द्वारा आहरित कर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी, सचिवालय परिसर, देहरादून को उपलब्ध कराई जायेगी।
- 4- एन०आई०सी० द्वारा उपरोक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों हेतु किया जायेगा, जो कार्य सक्षम स्तर से स्वीकृत हों तथा उपरोक्त प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।
- 5- कार्यों की मासिक प्रगति प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यों का अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- कार्यों पर होने वाले उक्त व्यय का सम्परीक्षण महालेखानियंत्रक, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उपयोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय।

7. वित्त विभाग के शासनादेश सं०-284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30.03.2012 में निहित निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।
8. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-12, 30 एवं 31 में अंकित लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-99-राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1080/XXVII(1)/2015, दिनांक 08 सितम्बर, 2015 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त (साफ्टवेयर आवंटन की प्रति सहित)

भवदीय,

(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव

संख्या-1502(1)/XXVIII-4/2015-51(11)/2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड।
3. मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, महानिदेशालय, देहरादून।
4. निजी सचिव-प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. प्रबन्धक-ई०एम०आर०आई०, हैदराबाद।
10. चीफ आपरेटिंग ऑफिसर, पं० दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-3/चिकित्सा अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(अतर सिंह)  
संयुक्त सचिव

(₹ हजार में)

क्र.सं.	लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
	<b>अनुदान सं0-12</b>	
1	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	46200
	06 लोक स्वास्थ्य	
	101 रोगों का निवारण एवं नियन्त्रण	
	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन	
	20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	
	<b>अनुदान सं0-30</b>	
2	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	11400
	06 लोक स्वास्थ्य	
	101 रोगों का निवारण एवं नियन्त्रण	
	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पी0पी0पी0	
	20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	
	<b>अनुदान सं0-31</b>	
3	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2400
	06 लोक स्वास्थ्य	
	101 रोगों का निवारण एवं नियन्त्रण	
	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन पी0पी0पी0	
	20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	
	<b>महायोग</b>	

(₹ छः करोड़ मात्र)

  
(अतर सिंह)  
संयुक्त सचिव